

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1410
दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

1410. श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

श्री बैजयंत पांडा:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) मंत्रालय यह किस प्रकार सुनिश्चित करता है कि ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत प्रदान की गई डिजिटल अवसंरचना और उपकरण सभी पंचायतों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की पंचायतों के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता - अनुकूल हों;
- (ग) क्या ई-पंचायत एमएमपी के ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन पर प्रभाव को और बढ़ाने के लिए इसके संबंध में कोई भावी विकास योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा अधिक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बहुभाषी ई-गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने पंचायत स्तर पर डिजिटल भागीदारी और सेवा परिदान में सुधार लाने के संबंध में इन पहलों की प्रभावशीलता और प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) पंचायत स्तर के पदाधिकारियों में डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफार्मों की सुलभता और उपयोगकर्ता संबंधी अनुकूलता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को मजबूत बनाना और जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी और शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। परियोजना का उद्देश्य पंचायतों के आंतरिक कार्य प्रवाह और मुख्य कार्यों को स्वचालित करना और उनके कामकाज में अधिक नागरिक-केंद्रितता लाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस पहल के तहत प्रमुख एप्लीकेशनों में से एक ई-ग्रामस्वराज है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों की योजना, बजट, लेखांकन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज के एकीकरण से विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करना संभव हुआ है।

(ख) और (च) मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत डिजिटल अवसंरचना और उपकरण सुलभ हों तथा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी पंचायतों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल हों:

- लो बैंडविड्थ-अनुकूलित, मोबाइल-उत्तरदायी वेब एप्लीकेशनों का विकास;
- एसआईआरडी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से आरजीएसए योजना के अंतर्गत पंचायत अधिकारियों का क्षमता निर्माण;
- नियोजन, गतिविधियों, व्यय और कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए मेरी पंचायत मोबाइल एप्लिकेशन का विकास;
- भारतनेट के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए दूरसंचार विभाग और राज्यों के साथ समन्वय।

पंचायत पदाधिकारियों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

- फीडबैक के आधार पर सरलीकृत उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस;
- बहुभाषी पहुँच के लिए एकीकृत भाषिणी;
- सहायता मॉड्यूल और मैनुअल प्रदान किए गए;
- राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय हेल्पडेस्क स्थापित किए गए;
- पुनरावृत्त अद्यतनों के माध्यम से निरंतर सुधार सुनिश्चित किए गए;
- भूमिका-आधारित कार्यप्रवाह और एसएमएस/ईमेल सूचनाएँ सक्षम बनाई गईं।

इन प्रयासों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर समावेशी और कुशल डिजिटल शासन को बढ़ावा देना है।

(ग) और (ङ) मंत्रालय उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाकर और परामर्शी, फीडबैक-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और भविष्य के विकास को प्राथमिकता देने के लिए, क्षेत्रीय कार्यशालाओं और हितधारक परामर्शों सहित विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ताओं से नियमित रूप से फीडबैक एकत्र किया जाता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों और पंचायत पदाधिकारियों से प्राप्त फीडबैक को नियमित रूप से शामिल किया जाता है। इन प्रयासों के तहत, मंत्रालय ने हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए शिमला, हैदराबाद और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। अपने ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों को मज़बूत बनाने के लिए विचार-विमर्श और रोडमैप तैयार करने हेतु, मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक उद्योग परामर्श कार्यक्रम, "मंथन" का भी आयोजन किया। महाराष्ट्र और लखनऊ में भी हितधारकों के साथ फोकस वार्ता आयोजित की गई। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाए रखने के लिए कई ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं। ये बातचीत ज़मीनी स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रणाली में सुधार और युक्तिकरण के लिए कार्रवाई योग्य फीडबैक एकत्र करने में सहायक रही हैं।

प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण में वृद्धि हुई है, योजना और लेखांकन में पारदर्शिता बढ़ी है, तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति में दक्षता बढ़ी है।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए बहुभाषी पहुँच बढ़ाने हेतु ई-ग्रामस्वराज को भाषिणी के साथ एकीकृत किया है। भाषिणी राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) के तहत विकसित एक AI संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में रीयल-टाइम भाषा अनुवाद और स्पीच टू टेक्स्ट सेवाएँ प्रदान करना है। यह एकीकरण पोर्टल पर निर्बाध भाषा अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पंचायत पदाधिकारी और नागरिक अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय समावेशी डिजिटल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और क्षेत्रीय भाषा डेटा प्रविष्टि को अपनाने में सहायता करता रहेगा।
